

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 013/2012 (GCMS 2012/00038)	दायर दिनांक 03.09.2012	निर्णय दिनांक 15.06.2022
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी****बनाम**

अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़।

**अप्रार्थी**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :- भैरूलाल सालवी  
विभागीय प्रतिनिधि

राजकीय अधिवक्ता  
अप्रार्थी

**--: निर्णय :-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म तालाब पेटा गे.मु. होकर गत भू-प्रबंध में बिलानाम सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 206 रकबा 0.12 हैक्टेयर बने जिसमें से आराजी नंबर 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर है जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में रास्ता (सडक) दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नंबर 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में रास्ता (सडक) दर्ज है जो माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 4 के विरुद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एवं पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये हैं जिसके अनुसार मौके की व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन कर उक्त आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन कर माननीय न्यायालय राजस्थाई हाई कोर्ट जोधपुर के निर्णयानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा



88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते हैं। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर को बिलानाम सरकार तालाब पेटा दर्ज की जावें।

इस पर प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.10.2012 को अप्रार्थी की और से विभागीय प्रतिनिधि हाजिर आये जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने बताया कि

आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज रेकार्ड राजस्थान सरकार है अप्रार्थी विभाग के नाम पर उक्त आराजी दर्ज नहीं है। आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है जो राजस्थान सरकार अर्थात् प्रार्थी के नाम पर दर्ज है अप्रार्थी विभाग के नाम पर दर्ज नहीं है जिससे अप्रार्थी विभाग को पक्षकार बनाया जाना गलत है। आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर जमाबंदी संवत् 2066-2069 खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार के नाम किस्म रास्ता दर्ज है। अप्रार्थी विभाग के नाम पर उक्त दर्ज नहीं होने से प्रार्थी अप्रार्थी से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का रेफरेंस इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावें। विपक्षी की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 15.06.2022 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म तालाब पेटा गे.मु. होकर गत भू-प्रबंध में बिलानाम सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 206 रकबा 0.12 हैक्टेयर बने जिसमें से आराजी नंबर 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर है जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में रास्ता (सडक) दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नंबर 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में रास्ता (सडक) दर्ज है जो माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 4 के विरुद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एवं पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये हैं।

इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि

आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज रेकार्ड राजस्थान सरकार है अप्रार्थी विभाग के नाम



पर उक्त आराजी दर्ज नहीं है। आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है जो राजस्थान सरकार अर्थात् प्रार्थी के नाम पर दर्ज है अप्रार्थी विभाग के नाम पर दर्ज नहीं है जिससे अप्रार्थी विभाग को पक्षकार बनाया जाना गलत है। आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर जमाबंदी संवत् 2066-2069 खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार के नाम किस्म रास्ता दर्ज है। अप्रार्थी विभाग के नाम पर उक्त दर्ज नहीं होने से प्रार्थी अप्रार्थी से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का रेफरेंस इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे, ऐसी अवस्था में आवेदन चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि परिपत्र दिनांक 16.07.2003 की पालना में जोहड़, तालाब, नाडी, आदि की भूमि को नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के निर्णयानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते हैं। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर को बिलानाम सरकार तालाब पेटा दर्ज की जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन/मनन/परिशीलन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मीठारामजी का खेडा पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की वर्तमान आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड होकर है, जो नियमों के विरुद्ध है जो नियमानुसार नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 का अवलोकन किया। अधिनियम की धाराओं में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :-

**82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board -**

The Settlement Commissioner or the Director of Land Records 61[or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;



and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement; and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

**232. Power to call for record and refer to the Board—**

The Collector may call for and examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and, if he is of opinion that the order or decree passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fit:

**Provided** that the power conferred by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट कि कि ग्राम मीठारामजी का खेडा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा में 3 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता दर्ज रेकार्ड मेवाड बंदोबस्त में दर्ज है जिसकी पुष्टि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2018-2022 से होती है। इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी द्वारा संपूर्ण राजस्व रेकार्ड का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी संख्या 206 रकबा 0.12 हैक्टेयर साबिक आराजी संख्या 85 मी. से बना हुआ है किन्तु आराजी संख्या 85मी0 रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा में 3 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता अंकित है इसके संबंध में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। एवं ना ही इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई साबिक रेकार्ड/नक्शा ट्रेस पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से



सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म तालाब पेटा की भूमि रही है अथवा नहीं ?

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म तालाब पेटा के साथ-साथ रास्ता की भूमि अंकित रही है इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार इस तथ्य को साबित कराये जाने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं कि उक्त भूमि किस प्रकार से किस्म रास्ता अंकित की गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का प्रार्थना सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है, किन्तु यह तथ्य पूर्ण रूप से न्यायालय के समक्ष परिलक्षित होता है कि उक्त विवादित आराजीयात आराजी संख्या 85 मी. किस्त पेटा दर्ज रही है। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण पुनः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को निम्नांकित निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है :-

- विवादित भूमि का संवत् 1993 के पश्चात् किस प्रकार से आवंटन/नियमन किया गया है एवं इस संबंध में संबंधित अभिलेख का परीक्षण कर यह निर्धारित करे कि प्रश्नगत आवंटन व नामान्तरकरण प्रक्रिया नियमानुकूल, वैध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?
- विवादित भूमि के जलोट या जलीय निकाय की होने की स्थिति की जांच आवंटन के समय के रेकार्ड एवं वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर किया जावे। समस्त दस्तावेजों, अभिलेख व तथ्यों के साथ आवश्यक हो तो, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिसमें अपेक्षित/संबंधित अभिलेख जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न हो एवं अधिनियम की धारा 232 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्यों को संयोजित करते हुए प्रार्थना पत्र बोलता हुआ (SELF SPEAKING) के रूप में "Reasoned and speaking" हो प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 15.06.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



-S/D-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़